Department Related Parliamentary Standing Committee on Industry, which presented its Report to Parliament in April, 1994. The various recommendations made in the Report are being considered by Government.

Meanwhile IISCO has become a sick industrial company in terms of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, and the Board of Directors of the company have made a reference to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) as required under section 15 of the Act for determination of measures to be adopted with respect to the Company. Any scheme to be taken up for modernisation of IISCO will therefore have to be in accordance with the orders of the BIFR in this rgard?

Suggestion of FICCI

1681. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the FICCI has recently suggested an action frame for boosting exports of value added steel products from India;

(b) if so, what are the deatils thereof; and

(c) what action Government propose to taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHN DEV): (a) and (b) In order to facilitate procurement of raw materials by steel product exporters from indigenous sources at international prices, FICCI has made the following suggestions:

(i) Exporting enterprises should be allowed to draw their raw material requirement from indigenous -producers against their duty free licences at the prevalent fob price, and

(ii) No sales tax should be charged against such supplies.

(c) Under the export-import policy, exporters already have the facility of duty free import of inputs for export production under the duty exemption scheme.

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभागीय स्टाकयार्ड खोलना

1682. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या इस्पात मंत्री यह बत ने की कृपा करगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभागीय स्टॉकयार्ड खोलने के लिये सरकार क्या मानदंड अपना रही है ;

(ख) इस समय सौराष्ट्र-कच्छ की औद्योगिक इकाइयों में विशेषत: गांधीधाम राजकोट की लोहा तथा इस्पात की कुल कितनी वार्षिक मांग है ;

(ग) क्या कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र लोहा और इस्पात की बढ़ती मांग को देखते हुये सरकार का विचार गांधीधाम में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का स्टाकयार्ड खोलने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो गांधीधाम में प्रस्तावित स्टाकयार्ड के कब तक खोले जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील आथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबंधन में विभागीय स्टाकयार्डों की स्थापना कई घटकों पर निर्भर करती जैसे आर्थिक व्यवहार्यता इस्पात खपत के संदर्भ में क्षेत्र की भावी संभावना इस्पात संयंत्रों से उपलब्धता की तुलना में बिक्री की संभावित वृद्धि, वर्तमान नेटवर्क के किसी भी मौजूदा वितरण केन्द्र से प्रस्तावित स्थान की वास्तविक समीपता आदि ।